राज रानी,- अपीलकर्ता।

बनाम

महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, करनाल
डिपो और अन्य,- प्रतिवादी।

1984 के आदेश क्रमांक 517 से प्रथम अपील

निर्णय की तिथि : 27-10-1988

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV)–एस.एस. 110, 110-ए(3)–दावा तीन महीने बाद दायर किया गया आवेदन- दुर्घटना के समान होने से इनकार किया गया पुलिस को सूचित नहीं किया गया–रिपोर्टिंग न करना–का प्रभाव–बताया गया।

माना गया कि कानून दावा याचिका दायर करने के लिए यह प्रावधान नहीं करता है-मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110 के तहत, दावेदार दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी होगी या दावेदार को देनी होगी दुर्घटना के तुरंत बाद तुरंत दावा याचिका प्रस्तुत करें। अधिनियम की धारा 110-ए(3) के तहत छह महीने की अवधि प्रदान की जाती है| दावा याचिकाएँ प्रस्तुत करना। दावा भीतर प्रस्तुत किया जाएगा उक्त अवधि. ट्रिब्यूनल के पास दावा स्वीकार करने की अतिरिक्त शक्ति है| यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो तो उस अवधि के बाद भी याचिका दायर की जा सकती है। क्ले-ऐसी परिस्थितियों में मंट को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया शीघ्र दावा याचिका दायर नहीं की। इसके अलावा, कानून दावेदार के उस बयान की आवश्यकता नहीं है. यदि यह

अन्यथा है|भरोसेमंद और विश्वसनीय, किसी भी स्वतंत्र द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए-सेंध गवाह. अन्य गवाहों को पेश न किया जाना संभव नहीं है| पीड़ित दावेदार के साक्ष्य को खारिज करने का आधार दिनदहाड़े हुई दुर्घटना में घायल।
(पैरा 4)

श्री के.सी.गुप्ता के न्यायालय के आदेश से प्रथम अपील,मोटर दुर्घटना, दावा न्यायाधिकरण, करनाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1984 जिला-श्रीमती का दावा आवेदन गुम है। राज रानी, धारा के तहत दावेदार-रुपये की वसूली के लिए धारा 110-ए. एक लाख मुआवजा और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देना।
दावा: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावा याचिका।अपील में दावा: मुआवज़ा बढ़ाने के लिए।

उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. बाली, अधिवक्ता रविंदर अरोड़ा,अपीलकर्ता के लिए.

बी.एस. मलिक, अतिरिक्त. ए.जी. (हाई.), श्री जे.सी. वर्मा, अधिवक्ता, के लिए प्रतिवादी क्रमांक 2.

आदेश

ए एल बहरी, जे.
इस अपील में, मोटर दुर्घटना दावों के पुरस्कार को चुनौती दी गई है| ट्रिब्यूनल, करनाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1984, -जिसके द्वारा दावा याचिका दायर की गई, श्रीमती राज रानी अपीलकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया। इस दौरान उनके पैर में चोट लग गई

प्रेम के पास बस स्टॉप पर हरियाणा रोडवेज की बस संख्या HYC-7123 में चढ़ना|22 दिसंबर 1982 को सुबह लगभग 8.30 बजे नगर ऑक्ट्रॉय पोस्ट, कमल। वह हरियाणा रोडवेज, करनाल में कार्यरत थी और अपनी ड्यूटी पर उपस्थित थी|बस से यात्रा करनी थी. उसने बस खिड़की की रॉड पकड़ ली थी|बोर्ड पर एक पैर रखा ही था कि बस अचानक चल पड़ी और तेज़ हो गई। बस को रवैल सिंह प्रतिवादी नंबर 2 और माई चंद द्वारा चलाया गया थाप्रतिवादी क्रमांक 3 कंडक्टर था। यह उसके कहने पर ही ड्राइवर ने किया था|बस वैसे ही चल पड़ी. उसने रुपये की राशि का दावा किया। मुआवजे के रूप में 1,00,000 और रुपये की राशि. अनुग्रह अनुदान के रूप में 7,500। उत्तरदाताओं ने इसका विरोध किया दावा इस बात से इनकार कर रहा है कि दुर्घटना उक्त बस से हुई थी जो कि थी|रवैल सिंह द्वारा संचालित। कुछ अन्य आपत्तियां भी उठाई गईं.ट्रिब्यूनल द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

1)क्या प्रश्नगत दुर्घटना जल्दबाजी के कारण घटित हुई हैबस क्रमांक HYC चलाते समय प्रतिवादी क्रमांक 2 की लापरवाही से गाड़ी चलाना-7123 एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 के कृत्य के कारण ? ओ.पी.पी.

2) दावेदार किस राशि के मुआवजे का हकदार है और कहां से?किसको ? ओ.पी.पी.

3) क्या दावा याचिका उचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है ? ओ.पी.आर.

4) क्या कोर्ट-फीस के प्रयोजनों के लिए याचिका का उचित मूल्यांकन किया गया है और क्षेत्राधिकार? ओ.पी.आर.

5)राहत.

(2) अंक संख्या 1 के तहत यह माना गया कि दुर्घटना नहीं हुई थीबस नंबर HYC-7123 के साथ। मुद्दा संख्या 2 के तहत, यह माना गया कि दावेदार

रुपये की मुआवजा राशि का हकदार था। 4,100. अंक क्रमांक 3 के अंतर्गत दावा याचिका को उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया माना गया। मुद्दा क्रमांक 4 के तहत दावा याचिका को उचित ठहराया गया न्यायालय-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्यवान। पर खोजने के मद्देनजर मुद्दा संख्या 1, जैसा कि ऊपर देखा गया, दावा याचिका खारिज कर दी गई।

3) मुद्दा संख्या 1 का निर्णय करते समय, ट्रिब्यूनल ने कथन को स्वीकार नहीं किया अपीलकर्ता राज रानी का इस आधार पर कि उसने दुर्घटना की सूचना नहीं दी थी| पुलिस और उसने लगभग तीन महीने बाद दावा याचिका दायर की दुर्घटना। अपने बयान में उसने कहा था कि उत्तरदाताओं के बाद दुर्घटना उसे मदद करने का आश्वासन दे रहे थे। चूँकि इस तथ्य को सामने नहीं रखा गया| उत्तरदाता जो R.W.I और R.W.2 के रूप में उपस्थित हुए, उनका कथन था| स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में अविश्वास किया गया। मैंने स्कैन कर लिया है|राजरानी का बयान और उसे स्वीकार्य मानते हैं, चिकित्सीय साक्ष्यों से भी पुष्टि होती है। दुर्घटना के तुरंत बाद,उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे भर्ती कराया गया। उसका बेड हेड टिकट तैयार किया गया था जिसमें उल्लेख था कि उसे चोट लगी थी, बस से गिरने का कारण|

4) कानून में यह प्रावधान नहीं है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत दावा याचिका दायर करने के लिए, दावेदार को पुलिस को दुर्घटना की रिपोर्ट करनी होगी या दावेदार को दुर्घटना के तुरंत बाद दावा याचिका प्रस्तुत करनी होगी। दावा याचिका प्रस्तुत करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए(3) के तहत छह महीने की अवधि प्रदान की गई है। दावा उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो न्यायाधिकरण को उक्त अवधि से परे दावा याचिका स्वीकार करने की और शक्ति है। ऐसे में दावेदार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने दावा याचिका तुरंत क्यों प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, कानून यह नहीं कहता है कि दावेदार के बयान, यदि वह अन्यथा भरोसेमंद और विश्वसनीय है, तो किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित होना चाहिए। अन्य गवाहों का उत्पादन न करना, यह साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसने दिन के उजाले में हुई दुर्घटना में चोटें आई थीं।

5) जे राजन रानीक का साक्ष्य जो 31 जस\पी.डब्लू.10 में उपस्थित हुए: इसेकैटेग कैल और उसके मामले का समर्थन करता है। उन्होंने के तरीके के बारे में बताया बस संख्या HYC-7123 के साथ दुर्घटना, जैसा कि ऊपर संक्षेप में वर्णित है।

6)पी.डब्ल्यू.पी.डब्ल्यू.एल. डॉ. एल.के.एस. एल. सचदेवा अपदस्थ राज रानी के अस्पताल में भर्ती होने पर बेड हेड टिकट बताया कि गिरने के कारण उसे चोट लगी थी बस से| नई कहानी के बारे में सोचने के लिए राजरानी के पास समय का कोई अंतराल नहीं था|यह बात तब कही गई जब वह पैर में फ्रैक्चर के कारण अस्पताल में भर्ती थी।राज रानी की गवाही स्वीकार करते हुए कि वह बस में चढ़ने ही वाली थी|जब यह अचानक शुरू हुआ और उसे चोटें लगीं, तो यह माना जाता है कि चोटें आईं बस की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उन्हें नुकसान हुआ। का कर्तव्य था|इसके बाद बस के कंडक्टर को ड्राइवर को बस शुरू करने का संकेत देना होगा|उसने यात्रियों और ड्राइवर को अंदर आने देने के लिए खिड़की बंद कर दी थी| यात्रियों को बैठाने के बाद बस चलानी चाहिए थी बस। इस प्रकार यह दुर्घटना बस को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण हुई हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा, जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं |राज रानी. इसलिए, मुद्दे नंबर 1 पर ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष उलट दिया गया है।

7) डॉ. के. एल. सचदेवा पी.डब्ल्यू. 1 के अनुसार, राज रानी को 22 दिसंबर, 1982 को शाम 4.25 बजे कैजुअल्टी विभाग के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 जनवरी, 1983 को उसका ऑपरेशन किया गया और वह 12 फरवरी, 1983 तक अस्पताल में रही। उसके बाएं पैर (पैर की) ऊरु गर्दन में फ्रैक्चर था। अस्पताल छोड़ते समय उसका पैर प्लास्टर में था। 17 जनवरी, 1983 को प्लास्टर में एक खिड़की बनाई गई और टांके हटा दिए गए। खिड़की बंद कर दी गई थी। मरीज पर पिन-ट्रैक्शन भी लगाया गया था। बयान 28 सितंबर, 1983 को दिया गया था और उस दिन भी राज रानी बैसाखी का इस्तेमाल कर रही थी। 6 फरवरी, 1984 को डॉक्टर की और परीक्षा की गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाया कि मरीज की विकलांगता साठ प्रतिशत तक है। अगर उसका फिर से ऑपरेशन किया जाता तो उसके ठीक होने की संभावना थी। इस विकलांगता के कारण वह अपने सामान्य कामकाज में शामिल नहीं हो पा रही थी। जिरह

के दौरान, उन्होंने कहा कि बिना ऑपरेशन के भी उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर के कारण पैर के छोटे होने के बारे में राय नहीं दी और कहा कि समय बीतने के साथ, फ्रैक्चर पूरी तरह से जुड़ जाएगा और मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मरीज की समग्र विकलांगता नहीं दी गई थी। डॉक्टर ने पैर की साठ प्रतिशत विकलांगता दी, हालांकि उन्होंने विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा। लगभग दो महीने तक राज रानी अस्पताल में रही। इस प्रकार, पैर में लगने वाली चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आकलन किया जाना है। ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवजे का आकलन 4,100 रुपये तक किया, जो किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए बिल्कुल भी अपर्याप्त नहीं है। यह सिर्फ मूल्यांकन किया गया मुआवजा है। ट्रिब्यूनल का इस संबंध में मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष, इसलिए, इस संबंध में पुष्टि करता है।

8)मुद्दे संख्या 3 और 4 पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई है|इसलिए, यह अपील और इसकी पुष्टि की जाती है।

9) ऊपर दर्ज कारणों से, यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है।वकील की फीस रु. 300. ट्रिब्यूनल का पुरस्कार संशोधित किया गया है। अपीलकर्ता रुपये की राशि की अनुमति है. प्रति वर्ष 12 प्रतिशत के साथ मुआवजे के रूप में 4,100 रु दावा याचिका शुरू होने की तारीख यानी 8 मार्च से उस पर ब्याज;1983 से साकार होने तक।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा